हवा में,

दि. 24.8.98

माननीय प्रधानमंत्री जी,
एवं प्रभारी मंत्री, कार्मिक एवं लोकशिकायत,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय मितव्ययता हेतु सुझाव

महोदय,

संघलोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग भर्ती बोर्ड सहित अनेक अभिकरणों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष लगभग पदों पर भर्ती होती है जिसमें लगभग 5 करोड़ आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं । प्रत्येक अभिकरण प्रत्येक अभ्यर्थी से अनेक प्रकार के दस्तावेज, प्रतिलिपियाँ, खाली लिफाफे, फोटो, डाक टिकिट तथा शुल्क ग्रहण करता है । इस प्रक्रिया में औसतन एक करोड़ रुपये के डाक लिफाफे तथा 2 करोड़ रुपये की डाक टिकटें तथा अन्य कागजात निरर्थक व्यय होते हैं ।

1. मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक पद के लिए आवेदनकर्ता से साक्षात्कार के पूर्व कुछ भी कागजात या उसकी प्रतिलिपियाँ न माँगी जाएँ न ही खाली लिफाफे तथा डाक टिकटें माँगी जाएँ । इससे तो अधिक अच्छा यह हो कि निर्धारित शुल्क में 2 रुपये अधिक ले लिये जाएँ । आवेदन पत्र पर अंकित सूचनाएँ केवल प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करे तथा राजपत्रित अधिकारियों से कुछ भी प्रमाणित न कराये । यह ब्रिटिश परम्परा हमें त्यागनी होगी । भर्ती अभिकरणों के पास आने वाले 95 % लिफाफे पता लिखा होने के कारण रद्दी में फेंके जाते हैं । इसी प्रकार प्रमाणित अन्य प्रतिलिपियाँ भी रद्दी में जाती हैं कागज की कमी से जूझता भारत 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष केवल इसी आधार पर क्यों व्यय करे ?

2. दूसरा सुझाव यह है कि एक समान पदों पर अलग-अलग भर्ती अभिकरणों द्वारा भर्ती करने के बजाए एक ही राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करें ताकि एक बेरोजगार को भिन्न - भिन्न जगहों पर आवेदन न करना पड़े । इससे प्रत्येक बेरोजगार का बार-बार होने वाला आवेदन तथा परीक्षा खर्चा तथा भर्ती मंडलों का प्रशासनिक व्यय संयुक्त होगा । यह राशि 3000 करोड़ रुपये वार्षिक बचत कराएगी ।

आशा है कि आप विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे ।

सादर

भवदीय --

डा. सुरेन्द्र कुमार कटारिया

पोस्ट बॉक्स नं. 20 / सीकर- 332001 राज.